पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 21, अंक 1–2/2020

सतत् उपभोग को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर देना होगा ज्यादा ध्यान

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 'कट्स' द्वारा 13 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया।

परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' द्वारा संचालित 'प्रोओर्गेनिक' परियोजना का हवाला देते हुए 'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने बताया कि इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय 'सतत् उपभोक्ता' है। दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित विषय हैं, क्योंकि यह सतत् उपभोग को इंगित करता है और उपभोक्ता को सततता की ओर ले जाता है।

अपने उद्बोधन में उन्होंने सभी को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण की सारी हदों को पार कर जलवायु परिवर्तन के ऐसे पायदान पर खड़े हैं, जहां पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव समुदाय का विनाश हो रहा है। उन्होंने बताया कि पेरिस समझौते के तहत हमने धरती के तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने व सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के वादों को तोड़ दिया है।

प्रोओर्गेनिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतत् उपभोग को बढ़ाना है जो कि उपभोक्ता जागरूकता और मांग व पूर्ति को बढ़ाने से संभव हो पाएगा। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों

के न्यूनतम उपयोग करने, प्लास्टिक के उपयोग को रोकने, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर जोर दिया।

'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी तथा राजदीप पारीक ने प्रोओर्गेनिक परियोजना के अन्तर्गत की गई गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को अवगत कराया। जिसमें किसान प्रशिक्षण एवं भ्रमण, जागरूकता गतिविधियां, स्कूलों में जैविक गार्डन विकसित करने तथा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट्स आदि शामिल हैं।

परिचर्चा में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक आर.के. यादवेन्द्र ने बताया कि जैविक खेती की मुहिम को उपभोक्ता, किसान और संस्थाओं को समझना होगा तथा एक साथ इसके लिए कोशिश करनी होगी। उन्होंने परम्परागत कृषि विकास परियोजना के तहत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी।

डॉ. ए.के. गुप्ता, निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ने 'कट्स' के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि परियोजना में किसान तथा उपभोक्ता दोनों के मुद्दों पर काम करने से परियोजना के परिणाम आशा के अनुरूप आ रहे हैं।

डॉ. गजेन्द्र शर्मा, सहायक अनुसंधान अधिकारी, कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा जैविक उत्पाद की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसका किसान फायदा उठा सकता है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में किचन गार्डन एवं छत पर बागवानी की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 'कट्स' द्वारा ग्रीन एक्शन वीक के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की।

परिचर्चा में राज्य सरकार के कृषि विभाग व दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान के अधिकारी, जैविक खेती पर काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा परियोजना के तहत विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं सहित 60 से अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, कार्यक्रम अधिकारी ने सभी आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा निमिषा शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

इस अंक में...

- गायब हो गया 17 हजार क्विंटल गेहूं 3
- 'आयुष्मान भारत' में सामने आया फर्जीवाड़ा .. 4
- सरकारी अफसरों में बढ़ रहा भ्रष्टाचार 5
- आम बजट 2020–21 की मुख्य घोषणाएं 7
- याद रहे पानी पर प्रधानमंत्री की पहल 10

विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर 'कट्स' द्वारा 5 जून 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का शुभारम्भ करते हुए 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने स्वागत उद्बोधन में विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष के विषय 'जैव विविधता में प्रकृति के लिए समय' के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्योंकि जैव विविधता को वर्ष 2011-2020 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रतीक के रूप में देखा गया है।

वेबिनार में 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप एस. महता ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आवश्यक है। आज जो जैव विविधता का असंतुलन हो रहा है, इसमें मुख्य घटक हमारी जीवन शैली में हो रहे बदलाव हैं।

वेबिनार में अनुभा प्रसाद, राष्ट्रीय समन्वयक, पेज, यू.एन.ई.पी. ने भारत में पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब एक लाख प्रजातियां पूरी दुनिया में विलुप्ति के कगार पर हैं।

वेबिनार में मारिया रिडलूंड, वरिष्ठ नीति सलाहकार, स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन, स्टॉकहोम ने बताया कि जैव विविधता का संरक्षण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का नुकसान बहुत तेज गति से हो रहा है और यह आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से प्रभावित करेगा।

वेबिनार में नाओमी स्कॉटमर्न्स, सतत् उपभोग प्रबन्धक, कन्ज्यूमर इंटरनेशनल, लंदन ने जैव विविधता संरक्षण एवं उपभोक्ताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज लोग पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व को समझ रहे हैं। गूगल द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस कोरोना महामारी काल में लोगों ने इस बात पर खोज की है कि सतत् उपभोग वाली जीवन शैली को कैसे जिया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद् एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. बालाकृष्णा पिसुपति ने वेबिनार में प्रकृति आधारित समाधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 जैव विविधता और प्रकृति संरक्षण के आस-पास केन्द्रित है। कोरोना महामारी के परिणामस्वरूप दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में जैव विविधता संरक्षण एक चुनौती है।

वेबिनार के समापन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति प्रकृति का अनुभव नहीं कर सकता है, तब तक वह प्रकृति के मूल्य को नहीं समझ सकता है। हमें अपना व्यवहार बदलना होगा। वेबिनार में देश के कई राज्यों और विदेशों में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये।

'कट्स' द्वारा पृथ्वी दिवस पर वेबिनार आयोजित

हर साल पूरे विश्व में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह दुनियाभर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। प्रसन्नता है कि इस वर्ष पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। वर्ष 2020 के लिए इस कार्यक्रम का विषय 'क्लाइमेट एक्शन' निर्धारित किया गया है।

'कट्स' द्वारा 22 अप्रैल 2020 को स्काइप के मंच का उपयोग करते हुए वेबिनार का आयोजन कर पृथ्वी दिवस मनाया गया। वेबिनार की शुरुआत करते हुए 'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि 22 अप्रैल, 1970 को पहला पृथ्वी दिवस आयोजित किया गया था, ताकि प्राकृतिक वातावरण और उसके संरक्षण के बारे में दुनियाभर में मानव जाति की भूमिका का निर्धारण कर जागरूकता बढ़ाई जा सके। आज यह कई संगठनों और समुदायों के लिए सामूहिक रूप से एक साथ एकत्रित होकर पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने, कूड़े-कचरे को साफ करने, पेड़ लगाने और प्रकृति की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने आदि के लिए एक लोकप्रिय दिन बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 'क्लाइमेट एक्शन' मानवता के भविष्य और सम्पूर्ण विश्व को रहने योग्य बनाने वाली जीवन-समर्थन प्रणालियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

सारा निल्सन, प्रोग्राम मेनेजर, एसएसएनसी, स्टॉकहोम ने जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव जाति, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के भविष्य को आकार देने वाले जलवायु परिवर्तन पर अपने अनुभवों को साझा किया। नाओमी स्कॉट-मर्न्स, सस्टेनेबल कंजम्पशन मैनेजर, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल और वन प्लैनेट नेटवर्क ने 1994 में ओस्लो संगोष्ठी पर प्रकाश डाला, जिसमें उपभोग की वस्तुओं, सेवाओं का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों, विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट के उत्सर्जन को कम करते हुए जीवन की बेहतर गुणवत्ता लाने के लिए टिकाऊ खपत की एक कार्यशील परिभाषा का उल्लेख किया गया है। वेबिनार में 'कट्स' इंटरनेशनल, जिनेवा के पदाधिकारियों सहित कई विद्वानों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए।

गायब हो गया 17 हजार क्विंटल गेहूं

गोदाम से राशन की दुकान के बीच लेखांकन में 2.66 करोड़ रुपए का 17 हजार क्विंटल गेहूं गायब मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक गेहूं पहुंचाने व भंडारण में इसका कोई हिसाब-किताब तक नहीं मिला। कैग ने इस गेहूं की चोरी की आशंका व्यक्त की है।

कैग रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर व उदयपुर में 12496 क्विंटल, अलवर-भरतपुर व चूरू में 1808 क्विंटल, भरतपुर में 1416 क्विंटल, राजगढ़ (अलवर) में 1161 क्विंटल गेहूं का लेखांकन कागजों में कम पाया गया। एजी (लेखापरीक्षा) ने विभागीय अधिकारियों के साथ 114 उचित मूल्य की दुकानों पर संयुक्त निरीक्षण भी किया और पाया कि सरकार ने गेहूं की गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी नहीं की। दुकानों में मिले गेहूं में अधिक मात्रा में कंकड़ और धूल होती है। *(रा.प., 16.03.20)*

सरकारी कर्मचारी खा रहे गरीबों का गेहूं

प्रदेश में डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी हर साल गरीबों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 36 हजार टन गेहूं खा रहे हैं। योजना 2013 में शुरू हुई थी। छह वर्षों का आंकड़ा देखें तो दो लाख टन से ज्यादा गेहूं ले चुके हैं।

शिकायत मिलने पर खाद्य मंत्री रमेश मीणा के निर्देश पर शासन सचिव खाद्य सिद्धार्थ महाजन ने तहसील स्तर पर सत्यापन का आदेश दिया है। अब जिलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े ऐसे परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है और वे स्वतः नाम कटवाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक करीब 70 हजार कर्मचारियों ने नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है। बड़ा सवाल यह है कि गेहूं ले रहे ऐसे कर्मचारियों से अब वसूली कैसे होगी? *(दै.भा., 10.01.20)*

लाखों खर्च फिर भी सूख गए पौधे

औद्योगिक क्षेत्र में रीको में हरियाली के लिए करवाया गया पौधारोपण दम तोड़ रहा है। आधे से भी ज्यादा पौधे सूख गए हैं। रीको ने पाली में पुनायता, मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ में 950 पौधारोपण के लिए एक प्राइवेट ठेकेदार को 36 लाख रुपए में ठेका दिया था।

ठेकेदार की लापरवाही से पौधे सूख गए। पौधों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ईंटों के ट्री-गार्ड भी टूट गए। प्रदूषण से निपटने के लिए जिस हरियाली की जरूरत है, सपना बन कर रह गई। ठेकेदार को पांच साल तक पौधों की देख-रेख करने, पौधों में समय पर नियमित पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी गई है।

(न.नु., 29.02.20)

कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में फर्जीवाड़ा

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश में चल रहे कई प्रशिक्षण केंद्रों में हाइटेक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। केंद्रों पर सिलिकॉन मैटेरियल पर प्रशिक्षणार्थियों की अंगूठा निशानी की हू-ब-हू नकल (थंब क्लोन) बना ली गई है। इन्हीं क्लोन से रोजाना फर्जी हाजरी करके लाखों रुपए की सरकारी सहायता राशि उठाने का खेल चल रहा है।

उल्लेखनीय है, इस योजना पर केंद्र व राज्य सरकारें बड़ा बजट जारी कर रही हैं। जिसमें बेरोजगार युवक-युवतियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर बजट खाने-खिलाने का ये सारा खेल चल रहा है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने अब ऐसे केंद्रों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। *(रा.प., 07.01.20)*

सोलर लाइट घोटाला-: नहीं हुई वसूली

प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में करीब पांच साल पहले हुए 60 करोड़ रुपए के सोलर लाइट घोटाले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग अभी तक महज 9 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाया है। जबकि 51 करोड़ रुपए की वसूली अभी तक भी नहीं हो पाई है।

गौरतलब है, वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के माध्यम से चिन्हित स्थानों पर सोलर लाइट लगाने के आदेश दिए थे। कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों ने सोलर लाइट खरीदने में करीब 60 करोड़ रुपए की अनियमितताएं की थी। जब जांच में यह घोटाला सामने आया, उसके बाद विभाग ने इस गबन राशि को वसूलने की कार्रवाई शुरू की थी। *(दै.न., 19.03.20)*

साफ पानी पिलाने के नाम पर घोटाला

शहरवासियों को साफ पानी पिलाने के नाम पर जलदाय विभाग में 50 रुपए में तारीख बदलने के पीछे करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। मौके पर टंकियां और टैंक भले ही सालों साफ नहीं हो रहे हों, लेकिन उनका साफ करने का ठेका समय से जरूर उठ जाता है और उसके बाद भुगतान भी हो जाता है। हर छह महीने में टेंडर होते हैं फिर भी सालों से टैंक साफ नहीं हो रहे।

पानी की टंकियों और टैंक पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत की तो अधिकतर ने स्वीकार किया कि पिछले एक दो सालों से कोई भी पानी की टंकी साफ नहीं हुई है। इतना ही नहीं विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं हैं कि टैंक साफ करने के लिए पानी की आपूर्ति रोकी गई हो।

(रा.प., 24.01.20)

कागज की खरीद में 'कालिख'

राज्य सरकार की ओर से गरीब बच्चों को निःशुल्क बंटने वाली पुस्तकों के लिए कागज खरीद में घालमेल जारी है। राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल कागज 67.98 रुपए प्रति किलो खरीद रहा है। जबकि अन्य सरकारी एजेंसियां इससे कम दर पर खरीदी कर रही है। ऐसे में सरकार को इस साल करीब 59 करोड़ रुपए अधिक भुगतान करना पड़ेगा।

मंडल ने पेपर खरीद के लिए दो तीन फर्मों को काम सौंपा है। फर्मों से 32 हजार मेट्रिक टन पेपर खरीदा जा रहा है। ऐसे में इन फर्मों को करीब 215 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान किया जाएगा। यदि एनसीईआरटी या फिर प्रदेश की गवर्नमेंट प्रेस की तर्ज पर कागज खरीदा जाता तो सरकार को 59 करोड़ रुपए की बचत होती। *(रा.प., 09.02.20)*

सरकारी विभागों में हुए निष्फल खर्च

सरकारी विभागों की ओर से विभिन्न कार्यों में कराए गए निर्माण कार्य बेकार हो गए। इसका खुलासा महालेखा परीक्षक द्वारा पेश प्रतिवेदन में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत वजीरपुरा टोंक में निर्मित महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए छात्रावास सुविधा सहित जिला प्रशिक्षण केन्द्र बनने के बाद 15 वर्ष तक अनुपयोगी रहा। इस कार्य में 1.51 करोड़ रुपए खर्च हुए।

इसी प्रकार संचालन व संधारण के अभाव में जोधपुर व फलोदी में स्थापित आरओ संयंत्र अकार्यशील हो गए। इसमें जन स्वास्थ्य व अभियान्त्रिकी विभाग का 1.53 करोड़ रुपए निष्फल रहा। रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर और पाली में विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निर्मित छात्रावास भी अनुपयोगी रहा। कोटा में सीवरेज परियोजना पर 77.78 करोड़ रुपए का खर्च अपूर्ण रहने से बेकार गया।

(दै.न., 07.03.20)

फाइलों में दबाया 'लॉयल्टी बोनस'

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत हजारों संविदाकर्मियों के लगभग 30 करोड़ रुपए फाइलों में ही दब कर रह गए। संविदाकर्मियों को 'लॉयल्टी बोनस' के तौर पर यह राशि दी जानी थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली मिशन की गवर्निंग बॉडी ने पिछले वर्ष नवंबर में ही 'लॉयल्टी बोनस' के मद में यह राशि संविदाकर्मियों को देने का फैसला कर लिया था। लेकिन दो माह से मिशन मुख्यालय और वित्त विभाग के बीच फाइल को फुटबॉल बना कर अटकाया जा रहा है।

योजना में केंद्र का 60 प्रतिशत और राज्य का 40 प्रतिशत वित्तीय प्रावधान है। गवर्निंग बॉडी की बैठक में माना गया था कि केंद्र ने 2017-18 और 2018-19 के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटशन प्लान में ही लॉयल्टी बोनस देने का प्रावधान कर लिया था। इसी आधार पर 2019-20 के लिए भी बोनस देने का स्पष्ट फैसला हो गया था। *(रा.प., 09.01.20)*

आरटीओ नहीं वसूल सका टैक्स

एयरपोर्ट के ऑपरेशन ऐरिया में विमानन कंपनियों के संचालित हो रहे अवैध वाहनों पर कार्रवाई होने के बावजूद आरटीओ ने टैक्स की वसूली अभी तक नहीं की। विमानन कंपनियों के 150 से अधिक वाहनों पर करीब 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया निकाला गया था।

जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा था वे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। दूसरे राज्यों के वाहन भी बिना टैक्स चुकाए चलाए जा रहे थे। एयरपोर्ट पर जिन वाहनों पर कार्रवाई की गई थी, वे यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल से हवाई जहाज तक एवं वापस हवाई जहाज से टर्मिनल तक ले जाने वाली बसें, दूसरे राज्यों के पंजीकृत वाहन, बेगेज ट्रॉली एवं ट्रांसपोर्ट में लगे ट्रैक्टर आदि थे। *(रा.प., 02.03.20)*

जल स्वावलंबन में घोटाला

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत बनाए जाने वाले जल संरक्षण ढांचे (पोखर तालाब) के निर्माण में धौलपुर जिले के बाड़ी की वन बिहार रेंज में तालाब बनाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। तालाब बनाने की 80 जगहों पर निरीक्षण करने पर सामने आया कि 50 जगहों पर तो तालाबों का कहीं नामोनिशान तक नहीं था। सिर्फ खाली मैदान पड़ा था। बाकी 30 जगह ऐसी थी जहां छोटे-मोटे खड्डे ही नजर आए।

इसमें ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 10 से ज्यादा जगह तो ऐसी है, जहां 3 साल पहले वन विभाग तालाब का निर्माण दिखाकर पैसे उठा चुका था। उन्हीं का दोबारा दो-तीन महीने पहले विकास कार्यों के तहत निर्माण दिखा कर पंचायत भी पैसे उठा चुकी है। अब इन्हीं तालाबों के भुगतान में कमियां बताकर फिर से वन विभाग के ठेकेदार ने करीब 80 लाख रुपए से ज्यादा के बिल तैयार करा लिए। कुछ बिलों का भुगतान भी हो गया। *(दै.भा., 07.02.20)*

बीमा ने किसानों के रोके 444 करोड़

केंद्र एवं राजस्थान सरकार की लापरवाही की कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। दोनों सरकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम के करीब 385 करोड़ रुपए नहीं चुकाए, जिसके चलते बीमा कंपनियों ने किसानों के फसल खराबे के करीब 444 करोड़ रुपए रोक लिए। ऐसे में किसान कई महीने बीतने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर हैं।

कांग्रेस और भाजपा किसानों को लेकर सियासत खूब करती है लेकिन उनके हालात सुधारने के गंभीर प्रयास कोई नहीं करता। दोनों सरकारों के नकारेपन के चलते समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। हालात यह है कि 2018 के खरीफ फसलों के बीमा प्रीमियम भी केंद्र व राज्य सरकार जमा नहीं करा सकी। इसी तरह के हालात 2018-19 के रबी फसलों के प्रीमियम को लेकर बने हुए हैं। *(रा.प., 17.03.20)*

'आयुष्मान भारत' में सामने आया फर्जीवाड़ा

सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' में फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। योजना में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के ही आईटी सिस्टम ने दो लाख से ज्यादा फर्जी गोल्डन कार्ड पकड़े हैं। जांच अभी शुरुआती दौर में है।

माना जा रहा है कि विस्तृत जांच होने पर यह आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। हालांकि एनएचए ने कुछ शुरुआती मामलों में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े के कई उदाहरण हैं। जैसे गुजरात में एक अस्पताल में आरोग्य मित्र ने एक ही परिवार के नाम पर 1700 कार्ड बना दिए। छत्तीसगढ़ में भी एक परिवार के नाम 109 कार्ड बन गए और इनमें से 57 ने आंख की सर्जरी भी करा ली। मध्य प्रदेश में भी एक ही परिवार के नाम 322 कार्ड बने हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ी यूपी, गुजरात, छग, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड में सामने आई है। *(दै.भा., 03.01.20)*

आरटीओ में की सबसे बड़ी कार्रवाई

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सवा सौ अधिकारियों व कर्मचारियों की 17 टीमों ने परिवहन विभाग पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर जिले सहित रेवाड़ी में 8 परिवहन अधिकारियों और 7 दलालों के यहां सर्च में 1.20 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है।

एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि चार माह पहले दलालों के जरिए वाहन मालिकों को डरा-धमका कर बंधी वसूलने की शिकायत मिली थी। इस आधार पर शाहजहांपुर डीटीओ गजेन्द्र सिंह, चौमूं डीटीओ विनय बंसल, मुख्यालय डीटीओ महेश शर्मा, परिवहन निरीक्षक शिव चरण मीणा, उदयवीर सिंह, आलोक बुढानिया, नवीन जैन और रतन लाल के घरों पर जांच की है। दलालों से लेन-देन की सूचियां, लैपटॉप व पैन ड्राइव भी मिले हैं। *(रा.प., 17.02.20)*

देश में करप्शन का सिस्टम बन गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी भी देश की तरक्की का आधार वहां की अर्थव्यवस्था होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है। देश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर चलते हैं।

गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स के राष्ट्रीय सेमिनार प्रकर्ष को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के तहत मिलने वाले चंदे पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि देश में करप्शन का सिस्टम बन गया है।

इसे रोकने के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स (सीए) आगे आएं। एक पारदर्शी व जवाबदेह सिस्टम बनाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को भी इस बारे में सामूहिक कदम उठाने चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त देश की कल्पना कर सकते हैं। *(दै.भा., 01.01.20)*

सरकारी अफसरों में बढ़ रहा भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसा ही रहा तो स्थिति संभालना मुश्किल होगा। सबको पता रहता है कि यह अधिकारी भ्रष्ट है लेकिन उसके खिलाफ शिकायत नहीं मिलती।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) खुद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सबूत जुटा कर आय से अधिक संपत्ति के केस बनाए। मुख्यमंत्री ने विडियो कांफ्रेंस के जरिए एसीबी के जयपुर चौकी कार्यालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात कही। *(रा.प., 25.06.20)*

भ्रष्टाचार का गठजोड़ बहुत गहरा

- *सरकारी तंत्र में भ्रष्ट अफसर भरे हैं, इनका गठजोड़ गहरा है।*
- *मुख्यमंत्री ने कहा एसीबी का भय नहीं होगा तो यह कम नहीं होगा। पिछले कार्यकाल में हम एसीएस गृह के नेतृत्व में चीफ विजिलेंस अफसर, जिलों में विजिलेंस अफसर नियुक्त करना चाहते थे। इस पर फिर से काम किया जाएगा।*
- *हर शिकायत की जांच करें।*

लॉकडाउन खुलते ही रिश्वत का खेल

लॉक डाउन में आवाजाही पर रोक के कारण रिश्वतखोरी का खेल भी मंदा रहा। अनलॉक के शुरू होते ही सामान्य गतिविधि चालू हुई तो रिश्वत का यह गंदा खेल भी पहले की तरह चल पड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की लगातार हो रही कार्रवाई से यह स्थिति सामने आई है। अप्रेल में लॉकडाउन की सख्ती से पालना होने पर रिश्वत का एक ही मामला सामने आया।

वहीं मई माह में लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई तो रिश्वत के चार मामले सामने आए। जून में अनलॉक शुरू होते ही शुरुआती 12 दिन में रिश्वत के 12 मामले सामने आए हैं। अनलॉक 1.0 में एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे लगातार कई बड़े मामले भी सामने आने लगे हैं। *(रा.प., 15.06.20)*

भ्रष्टाचारियों पर कसा शिकंजा

प्रदेश में अब हर आमजन घूसखोर या आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करवा पाएगा। आमजन की ओर से दी गई सूचना सही पाए जाने पर एसीबी तुरंत कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1064 जारी किया है।

एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के मुताबिक ब्यूरो ने इस साल प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर स्तर पर कड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2019 में 424 अभियोग पंजीबद्ध किए गए हैं, जबकि पिछले साल 372 मामले दर्ज किए गए थे। *(दै.न., 01.01.20)*

भ्रष्ट अधिकारियों का हो रहा है बचाव

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बार-बार दिए गए निर्देश और राज्य सरकार के सर्कुलर के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एसीबी को समय पर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही। अधिकांश विभाग भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाने में जुटे रहते हैं। समय पर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने पर पीड़ित को न्याय मिलने में देरी होती है, साथ में साक्ष्य और गवाहों के प्रभावित होने की आशंका रहती है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की तीन माह में अभियोजन स्वीकृति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि मनाही की स्थिति में कारण बताने होंगे। सरकार ने इस बारे में सर्कुलर भी निकाला। लेकिन इसका असर नजर नहीं आया। एसीबी सूत्रों के अनुसार प्रदेश में विभिन्न विभाग 252 मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की अभियोजन स्वीकृति के मामले दबाए बैठे हैं। *(रा.प., 28.06.20)*

हर साल करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं ट्रक ड्राइवर

देश की सड़कों पर भारी संख्या में चल रहे ट्रक बेहद सुरक्षित स्थिति में चलाए जा रहे हैं। साथ ही देश में भ्रष्टाचार को भी ये बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक ट्रक के मालिक और ड्राइवर पुलिस और सरकारी एजेंसियों को सालाना लगभग 48 हजार करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। यह सेव लाइफ फाउंडेशन की ट्रक ड्राइवरों के काम करने की स्थिति और उनकी सुरक्षा पर जारी रिपोर्ट से खुलकर सामने आया है।

अध्ययन के मुताबिक देशभर में ट्रक ड्राइवर औसतन प्रत्येक लंबी ट्रिप में 1257 रुपए की रिश्वत देता है। इस लिहाज से सबसे ऊपर है गुवाहाटी, जहां यह रकम 2360 रुपए है। दूसरे स्थान पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहां के ट्रक ड्राइवरों को लंबी फेरी में औसतन 1803 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अध्ययन के अनुसार देश में सालाना 47,852.28 करोड़ रुपए ट्रक ड्राइवर और मालिकों की ओर से रिश्वत में दिए जा रहे हैं। *(रा.प., 29.02.20)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बूंदी	नीरज शर्मा	ग्राम विकास अधिकारी, धोवड़ा ग्राम पंचायत	44,000	दै.भा. एवं दै.न., 09.01.20
कोटा	मनोहर लाल जाट	एएसआई, पुलिस थाना रामगंज मंडी	20,000	दै.भा. एवं दै.न., 09.01.20
अलवर	जितेन्द्र यादव बलबीर यादव	थानाधिकारी, नारायणपुर थाना दलाल, मोरड़ी की ढाणी निवासी, नारायणपुर	90,000	दै.भा., 10.01.20
कोटा	एम.पी. वर्मा वीरम गुर्जर विजय गुर्जर	फॉरेस्ट गार्ड, वन विभाग, कोटा दलाल, धर्मपुरा रोड निवासी दलाल, चाय की थड़ी, धर्मपुरा रोड	25,000	दै.भा., 24.01.20
सीकर	अक्षय कुमार शर्मा सुरेश स्वामी	अधीक्षक, सीजीएसटीद्ध दलाल	50,000	दै.न., 01.02.20
सीकर	श्रवण सिंह मावलिया	संचालक, जगन टीटी बीएड कॉलेज, आलोदा	20,000	रा.प. एवं दै.न., 11.02.20
उदयपुर	भंवर लाल विश्नोई	थानाधिकारी, खेरवाड़ा थाना, उदयपुर	2,50,000	रा.प. एवं दै.भा., 12.02.20
अजमेर	विजय कुमार	कांस्टेबल, जसवंतगढ़ थाना, डीडवाना सर्किल	50,000	दै.न., 27.02.20
भीलवाड़ा	सौमित्र दाधीच	पटवारी, हमीरगढ़, भीलवाड़ा	1,51,000	रा.प. एवं दै.न., 07.03.20
नागौर	लक्ष्मण सिंह प्रेमसुख डिडेल सुरेश पारीक	आयकर अधिकारी, आयकर विभाग इंस्पेक्टर, आयकर विभाग सीए, बिचौलिया	4,00,000	दै.भा. एवं रा.प., 13.03.20
झालावाड़	प्रशान्त यादव	प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग, झालावाड़	10,000	रा.प., 14.03.20
टोंक	देवकी नन्दन शर्मा	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तिलांजू	15,000	रा.प. एवं दै.न., 18.03.20
जयपुर	अब्दुल कुद्दूस	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर कार्यालय	34,000	रा.प., 05.06.20
जयपुर	लक्ष्मण सिंह	परियोजना निदेशक, राज्य सड़क विकास प्राधिकरण	3,65,000	रा.प., 12.06.20
जयपुर	प्रमोद शर्मा	निवासी मालवीय नगर (डीआइजी के बेटे का दोस्त)	5,00,000	रा.प., 25.06.20
टोंक	शिवराम सिंह यादव सीता राम अग्रवाल	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व्याख्याता, बिचौलिया	50,000 46,000	रा.प., 25.06.20
चूरू	वीरपाल सिंह सुरेन्द्र सिंह	विकास अधिकारी, पंचायत समिति चूरू ग्राम सेवक	27,000	रा.प., 26.06.20

आम बजट 2020-21 की मुख्य घोषणाएं

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में जीरो बजट फार्मिंग, किसानों की आय दोगुनी करने, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, स्टार्टअप और स्वरोजगार से रोजगार सृजन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने और नई शिक्षा नीति लागू करने की बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आयुष्मान योजना का बजट बढ़ाने, सामाजिक कल्याण को अहमियत देने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का भी वादा बजट में शामिल है।

खेती और किसान को दी अहमियत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा करके उनके जीवन में उजाला कर चुकी है। वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य है।

जीरो बजट, जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा। बजट में गांव और किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा कर किसान की तकदीर बदलने का सपना देखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार कर इसके दायरे में 20 लाख किसानों को और कवर किया जाएगा। सरकार 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पम्प लगाने में मदद करेगी। किसान बंजर भूमि में सौर ऊर्जा संयत्र लगा सकेंगे। अतिरिक्त पैदा हुई बिजली को बेच भी सकेंगे।

महिला व बाल विकास पर फोकस

बजट में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए 28 हजार 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि महिलाओं के विकास से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रम और योजनाओं पर खर्च होगी। महिला एवं बाल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए 35 हजार 600 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों तक पहुंचने के लिए स्मार्ट फोन दिए गए हैं। ताकि पोषण आहार से जुड़ी जानकारी का ब्यौरा जुटा सकें।

बजट में महिला स्वयं सहायता समूहों के हाथों में भंडारण व्यवस्था होगी। यह उन्हें 'धान्यलक्ष्मी' का स्थान देने का प्रयास है। उनके द्वारा संचालित किए जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम से गांव के किसानों को फायदा मिलेगा। इस नई योजना में उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 'वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना पर फोकस किया जाएगा, ताकि मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। जन-धन बैंक खाते वाली स्वयं सहायता समूह की हर महिला सदस्य को मुद्रा योजना के तहत एक लाख तक के लोन की पात्रता को जारी रखा गया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' मिशन के नतीजे सुखद रहे हैं। इस मिशन पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द

बजट में नई शिक्षा नीति को इस बार फिर से दोहराया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह कब अस्तित्व में आएगी। वित्त मंत्री ने कहा इसके बेहतर प्रबंधन के लिए अधिक फंड की आवश्यकता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने की बात भी कही गई है। उच्चतर शिक्षा को समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए केंद्र ने 4447 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है। अब बजट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक 99 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इससे स्कूल-कॉलेजों में बेहतर संसाधन मिल पाएंगे। राष्ट्रीय क्वांट्स टेक्नोलॉजी मिशन में आठ हजार करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड पर जोड़ने का प्रस्ताव है। कौशल शिक्षा के लिए तीन हजार करोड़ का प्रावधान बताता है कि कौशल शिक्षा पर सरकार की प्राथमिकता है। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है।

अब खुद चुनना होगा आयकर स्लैब

अब करदाता को पुराने या नए आयकर स्लैब में से खुद को एक विकल्प चुनना होगा। उसे स्वयं को गणित लगानी होगी कि उसके लिए पुराना विकल्प फायदेमंद रहेगा या नया विकल्प। अगर किसी की आय पांच लाख से ज्यादा नहीं है (कटौति और कर छूट का दावा करने के बाद आय) तो आयकर एक्ट की धारा 87ए के तहत 12,500 रुपए तक कर छूट मिलेगी। अर्थात् दोनों विकल्पों में 5 लाख रुपए की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने करदाता को मर्जी का मालिक बनाया है। आयकर को आसान बनाने के साथ रेट में भी कमी की गई है। बचत आधारित जीवनशैली वाले करदाताओं के लिए पुराना विकल्प मौजूद रहेगा। नया विकल्प लेने वालों यानी ज्यादा खर्च करने वालों को पूर्व की तुलना में 5 से 10 फीसदी तक का कम कर चुकाना होगा।

इससे स्पष्ट है कि करदाता को अपनी वार्षिक आय के अनुसार स्वयं को दोनों विकल्पों में गणित लगा कर देखना होगा कि किस विकल्प के चुनने से उसे ज्यादा फायदा होगा।

मिलते रहेंगे सस्ते मकान

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने सभी के लिए सस्ते मकान की खरीद में लिए गए ऋण के भुगतान के ब्याज में 1 लाख 50 हजार रुपए तक की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। इस अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने के लिए ऋण की तिथि को 31 मार्च, 2020 से एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। अर्थात् मकान खरीदने वालों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी यह लाभ मिलता रहेगा।

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर एक नजर

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट रखा। खासकर, राज्य सरकार इस बार प्रदेश के विकास के लिए बजट में घोषित निम्न सात संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेगीः

1. निरोगी राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहला संकल्प लेते हुए कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट में 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया जाएगा।

इसमें से एक-एक करोड़ रुपए हर जिले को अभियान के प्रबंधन, प्रचार-प्रसार, एवं गोष्ठियां आयोजित करने के लिए मिलेंगे। प्रदेश के जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर एमआरआई व सीटी स्कैन की सुविधा मिल सकेगी। अगले चार साल में नए बनने वाले सभी 15 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर पांच हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देगी बाकी हिस्सा राज्य सरकार को खर्च करना होगा।

2. संपन्न किसान

कृषि व किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए तीन हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है।

किसानों की आय में वृद्धि, विपणन व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन, खेती को जोखिम रहित बनाने और किसानों व खरीददार के बीच लाभकारी व्यवस्था बनाने के मकसद से दो नए अधिनियम लाए जा रहे हैं। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए 25 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए 12 हजार 500 फार्म पौण्डों का निर्माण कराया जाएगा। दो लाख टन यूरिया और एक लाख टन डीएपी के अग्रिम भण्डारण के लिए 30 करोड़ और ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 91 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है।

3. महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण

प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को पोषाहार वितरित किया जाएगा। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा की है।

करीब 4 लाख 22 हजार से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिस पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाल अधिकार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 100 करोड़ रुपए से नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन किया जाएगा।

4. सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान

बजट में फिट राजस्थान, हिट राजस्थान का लक्ष्य रखते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें आगे लाने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे राज्य खेल ज्यादा सफल हों सकेंगे।

इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाएगा। प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए एवं कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है।

पहले यह राशि क्रमशः 75 लाख, 50 लाख व 30 लाख रुपए थी। प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना व औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा।

5. शिक्षा का परिधान

शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए बजट में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त संकाय और 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त विषय जरूरत के मुताबिक खोले जाएंगे। इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवाओं के लिए स्किल बढ़ाने और ट्रैनिंग कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। इसमें राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10 हजार विद्यार्थियों को ट्रैनिंग दी जाएगी।

6. पानी बिजली व सड़कों का ध्यान

बजट में पेयजल के लिए 8794 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए 16 जिलों की 30 परियोजनाओं के काम शुरू होंगे। इसमें 4 हजार 327 गांवों एवं 9 हजार 159 ढाणियों के लगभग 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। इस काम में 1 हजार 350 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति के लिए 625 करोड़ की लागत से काम कराए जाएंगे। बजट में 4557 करोड़ रुपए का प्रावधान जल संसाधन के लिए है।

ऊर्जा विभाग के लिए 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान बजट में है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 30 हजार मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 400 करोड़ रुपए से सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। 4245 करोड़ रुपए से पीएमजीएसवाई के तहत 8663 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

7. कौशल एवं तकनीक प्रधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 229 राजकीय आईटीआई में ई-क्लास रूम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण के गठन की घोषणा की। स्टार्टअप के विकास के लिए 75 हजार करोड़ रुपए के राजीव गांधी फंड की स्थापना की जाएगी।

बिजली चोरी में हुई कमी

प्रदेश में सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंधन की सख्ती व सिस्टम के सुधार के बाद मार्च, 2019 की तुलना में बिजली छीजत दो फीसदी तक कम हुई है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में वर्तमान वित्तीय साल में बिजली सप्लाई व बिलिंग की गणना करने के बाद जनवरी 2020 के अंत तक 18.06 फीसदी बिजली छीजत सामने आई है।

डिस्कॉम प्रबंधन ने मार्च के अंत तक ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का आंकड़ा 15 फीसदी तक लाने का टारगेट दे रखा है। ऊर्जा विभाग व बिजली कंपनियों ने भी उदय योजना में बिजली छीजत 15 फीसदी तक लाने का वादा कर रखा है।*(दै.भा., 02.03.20)*

विकसित होगा दूसरा बड़ा सोलर पार्क

सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्थान में बड़ी कंपनियों को लाने का काम शुरू हो गया है। नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) राजस्थान में 925 मेगावॉट क्षमता का सोलर पार्क विकसित करेगा।

प्रदेश में भड़ला के बाद दूसरा बड़ा सोलर पार्क जैसलमेर के नोखा में स्थापित किया जाएगा। इस पर चार हजार करोड़ का निवेश होगा। इसमें से 3500 करोड़ रुपए का निवेश एनटीपीसी करेगी जबकि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

(रा.प., 20.02.20)

कोरोना में हुनर आया काम

जहां कुछ कर गुजरने की चाह होती है वहां राह भी अपने आप खुल जाती है। यह साबित कर दिखाया सीकर के कोटड़ी लुहारवास निवासी राजकुमार योगी ने। वह पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में टाइल लगाने का काम से जुड़े थे। वह अपने गांव आए तो उन्हें यह रोजगार नहीं मिला।

उन्होंने अपने पुराने अनुभव को काम में लेते हुए बिजली फिटिंग का काम शुरू कर दिया। फिलहाल उन्हें 500-600 रुपए प्रतिदिन मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में उनको 800 रुपए मिलते थे, लेकिन कम आमदनी में भी घर पर रह कर वह काफी खुश हैं। *(रा.प., 29.06.20)*

बिजली बिलों के विवादित मामले

कोरोना महामारी को लेकर हुए 'लॉकडाउन' के कारण प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में सेटलमेंट कमेटियों की बैठकें स्थगित हैं। ऐसे में डिस्कॉम व उपभोक्ताओं के बीच बिजली बिल व सीसीआर के विवादित 20 हजार से भी ज्यादा मामले फंस गए हैं।

इन मामलों पर लॉकडाउन हटने के बाद ही सुनवाई हो पाएगी, लेकिन उनकी बकाया राशि पर लगने वाली पेनल्टी व विलंब शुल्क को लेकर सरकार के स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

उपभोक्ताओं की दलील है कि लॉकडाउन के कारण भविष्य में तय होने वाली राशि पर ब्याज, पेनल्टी व विलंब शुल्क नहीं लगे। व्यापारियों का भी कहना है कि कोरोना वायरस के कारण ठप पड़े उद्योगों व दुकानों के मद्देनजर बिजली बिलों में स्थाई शुल्क को माफ किया जाए।

(दै.भा., 08.04.20, 11.04.20)

हर घर महंगा उजियारा

प्रदेश में हर घर में घाटे की बिजली महंगा उजियारा कर रही है। डिस्कॉम कंपनियां खुद को घाटे में बताते हुए हर बार बिजली के दाम बढ़ा रही है। इससे आमजन की जेब पर करंट के झटके लग रहे हैं।

हालात यह है कि सस्ती रोशनी के लिए तरसती जनता को न तो सरकार का सहारा मिल रहा है और न ही डिस्कॉम का। दूसरी ओर सरकार डिस्कॉम को सहायता के नाम पर करोड़ों रुपए की मदद कर रही है।

विद्युत वितरण निगमों के घाटे से उबारने के लिए केंद्र ने उदय योजना शुरू की। इसमें विद्युत वितरण निगमों को 30 सितंबर 2015 तक बकाया ऋणों में से 75 प्रतिशत ऋणों का 50 प्रतिशत वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से अधिगृहित किए गए।

इसका उद्देश्य निगमों की स्थिति को बेहतर करना था। इसके बावजूद बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। *(रा.प., 20.01.20)*

बिजली दरें बढ़ी, किसानों व गरीबों पर नहीं पड़ेगा असर

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को बिजली की दरें बढ़ाने की इजाजत दे दी है। बिजली दरों में औसतन 11 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके अलावा मासिक फिक्स चार्ज भी 220 रुपए प्रति माह की जगह 275 रुपए प्रति माह किया गया है। नई दरें तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर में एक फरवरी से लागू होंगी।

राज्य के 20 लाख बीपीएल परिवार, 42 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और 14 लाख किसानों पर इस बढ़ोतरी का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। इनकी बढ़ी हुई दरों का भार सरकार उठाएगी। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने दावा किया है कि करीब 57 फीसदी यानी 76 लाख उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि का भार नहीं पड़ेगा। *(रा.प.एवं दै.भा., 07.02.20)*

उत्पादकों पर डिस्कॉम का बोझ

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादकों का बकाया अप्रैल 2020 में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 63 प्रतिशत बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो इस क्षेत्र में दिक्कतों को दर्शाता है। बिजली कारोबार में पारदर्शिता के लिए तैयार किए गए पोर्टल 'प्राप्ति' के मुताबिक अप्रैल 2019 में बिजली उत्पादकों का डिस्कॉम का बकाया 75,642 करोड़ रुपए था।

इस पोर्टल की शुरुआत मई 2018 में हुई थी ताकि बिजली उत्पादकों और डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद के लेन-देन में पारदर्शिता लाई जा सके। प्राप्ति पोर्टल के मुताबिक अपैल 2020 में कुल बकाया राशि, जो 60 दिनों की अनुग्रह अवधि के बाद भी चुकाई नहीं गई थी, बढ़कर 1,08,487 करोड़ रुपए हो गई।

(रा.प., 29.06.20)

बढ़ गया जयपुर का भूजल स्तर

नीति आयोग की जल संकट से जुड़ी रिपोर्ट के बीच जयपुर के लिए खुश खबर है। अच्छी बारिश से जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2019 में चिन्हित जगह पर 2.69 मीटर जल स्तर बढ़ा है, जो वर्ष 2018 की तुलना में 2.01 मीटर ज्यादा है। दूदू के लादेरा में जल स्तर एक साथ 22.6 मीटर ऊपर पहुंच गया।

यहां मानसून के पहले कम से कम 24.9 मीटर गहराई पर पानी मिल रहा था। वर्षों बाद जयपुर शहर के ज्यादातर इलाकों में भी भूजल स्तर सुधरा है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास एवं आस-पास के इलाके में भी 2.23 मीटर भूजल ऊपर आ गया है। विभाग ने जिले में पीजोमीटर लगा रखे हैं। इन्हीं के जरिए भूजल स्तर का आकलन किया गया है। *(रा.प., 06.02.20)*

गर्मियों में पेयजल संकट की आशंका

गर्मियों में प्रदेश के करीब 134 शहर-कस्बों और 14 हजार गांवों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। इन क्षेत्रों के लिए जलदाय विभाग ने चार माह जल परिवहन के लिए 6512.93 लाख रुपए का प्लान स्वीकृत किया है। इस प्लान के जरिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रेल से जुलाई 2020 तक पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4112.46 लाख तथा शहरी इलाकों के लिए 2400.47 लाख रुपए की स्वीकृति शामिल है। दरअसल जलदाय विभाग के अनुसार गर्मियों में 14 हजार 332 हैबीटेशंस में पेयजल की किल्लत हो सकती है। इसी तरह 134 शहर-कस्बों में वैसे तो अभी पानी की किल्लत नहीं है लेकिन मानसून में देरी या कमी होने पर पानी की परेशानी हो सकती है। *(दै.न., 01.04.20)*

झगड़े में अटका हमारे घर का पानी

केंद्र और राज्य के झगड़े में हमारे घर का पानी अटका हुआ है। दोनों सरकारों के बीच अनुदान का विवाद गहरा गया है। इससे 'हर घर नल, हर घर जल' योजना के समय से पूरे होने की उम्मीद दिखाई नहीं देती।

जलदाय मंत्री बी.डी.कल्ला का कहना है कि यदि केंद्र 90 प्रतिशत अनुदान नहीं देगा, तो चार साल तो क्या 20 साल में भी योजना पूरी नहीं कर पाएंगे। केंद्र अनुदान के रूप में कुल राशि का 50 फीसदी दे रहा है, राज्य सरकार 90 फीसदी अनुदान मांग रही है। वहीं जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विफलता छिपाने के लिए राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। 2013 से पहले पेयजल योजनाओं में 90 फीसदी अनुदान मिलता था। 14 वें वित्त आयोग के बाद इसमें बदलाव हुआ है। *(रा.प., 05.06.20)*

याद रहे पानी पर प्रधानमंत्री की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी के जन्म दिवस पर अटल भूजल योजना की शुरुआत करते हुए लोगों से जल संरक्षण को भी उसी गंभीरता से लेने की बात कही है, जिस गंभीरता से उन्होंने स्वच्छता अभियान को लिया था। उन्होंने किसानों को पीढ़ियों से चले आ रहे पानी की बर्बादी वाले सिंचाई के तरीके को बदलकर केवल पौधों की जड़ में पानी डालने की अपील की है। यह तरीका जल अल्पता वाले देश इस्राइल ने ईजाद किया था।

उन्होंने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे बहुत ज्यादा पानी सोखने वाली फसलों की जगह अन्य फसलें पैदा करना शुरू करें। यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी है, लेकिन पानी का हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पूरे देश में पानी की खपत का 89 फीसदी उपयोग खेती में होता है।

(दै.भा., 03.01.20)

बाड़मेर से जैसलमेर पानी का भंडार

प्रदेश के थार रेगिस्तान में बाड़मेर से जैसलमेर तक भूगर्भ में करीब 482 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होने का अनुमान है। इससे 100 साल तक पश्चिमी राजस्थान में पानी की किल्लत नहीं होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार भूगर्भीय विस्तार वाले इस भंडार की सबसे बड़ी चुनौती इसका खारापन है। अब केंद्र सरकार के पैट्रोलियम एवं जलशक्ति मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से राज्य की किस्मत बदलने वाली है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय के अधिकारियों ने एक प्रजैन्टेशन के जरिए उक्त जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान में कार्यरत ओआईएल, एचपीसीएल, केयर्स वेदांता समेत अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि व जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।

(दै.न., 07.03.20)

पानी की सुरक्षा के लिए जल्द लागू होगा नया कानून

राजस्थान में सतही व भूजल दोहन को रोकने और उसकी सुरक्षा के लिए जल्द नया कानून लागू होगा। यह राजस्थान वॉटर (कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रेग्यूलेशन) एक्ट होगा, जिसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री (बतौर मंत्री) को भेजा गया है। विधानसभा के मौजूदा सत्र के तत्काल बाद इसे फाइनल किया जाएगा। अभी पानी से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा एक्ट हैं। सरकार की मंशा है कि कम से कम एक्ट हों और उनकी प्रभावी रूप से पालना कराई जा सके।

राजस्थान में तेजी से कम होते भूजल से जुड़ी नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने इसमें तेजी दिखाई है। खास यह है कि यह एक्ट बनने के बाद सतही व भूजल दोनों एक ही एक्ट की जद में होंगे। अभी भूजल दोहन रोकने, उसके संरक्षण के लिए किसी तरह का कानून ही नहीं है। इसमें न केवल सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि आमजन भी इसकी जद में होगा। पानी बचाना अनिवार्य हो जाएगा। पानी का दुरुपयोग, दोहन करने और परिशोधन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा।

(रा.प., 06.03.20)

महिलाओं का बढ़ा मनरेगा में रुझान

कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में श्रमिकों के सामने पैदा हुए रोजगार के संकट में मनरेगा योजना काफी मददगार सिद्ध हो रही है। श्रमिकों के बढ़ते रुझान के बीच महिला श्रमिकों की तरफ से काम की ज्यादा मांग बनी हुई है। विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में महिलाओं की अधिक डिमांड बढ़ने से सभी जिलों में जॉबकार्ड जारी करने और डिमांड के हिसाब से काम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने भी आश्वस्त किया है कि योजना में पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी जिला कलेक्टरों को सभी श्रमिकों को तुरंत काम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कोरोना संक्रमण के बाद कई जिलों में महिला श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। *(दै.न., 15.04.20)*

विद्यार्थियों के घर पर पहुंचेगा खाद्यान्न

प्रदेश में पहले लॉकडाउन और बाद में ग्रीष्मावकाश के कारण पोषाहार (मिड-डे-मील) से वंचित रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। बच्चों के हिस्से का खाद्यान्न अब उनके माता-पिता को स्कूलों में बांटा जाएगा।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की मांग पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्यान्न वितरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को खाद्यान्न विद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। *(रा.प., 12.06.20)*

बनेंगे 75 लाख स्वयं सहायता समूह

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वर्ष 2022 तक देश में कुल 75 लाख महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे।

उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रीढ़ बताते हुए कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले समूहों को प्रोत्साहित करने के मकसद से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते छह साल के दौरान स्वयं सहायता समूहों को 2.75 लाख करोड़ से भी अधिक का ऋण प्रदान किया गया। *(न.नु., 12.03.20)*

बच्चों को बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत

यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है 2018 में देश में पांच साल से कम उम्र वाले 8.80 लाख बच्चों की मौतें हुई। यूनिसेफ की चिल्ड्रन फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे या तो कुपोषित हैं या मोटापाग्रस्त हैं।

हाल ही राजस्थान के कोटा व जोधपुर में सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए। पूरे देश की राजनीति एकदम गर्मा गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं बताई। देश में शिशु व मातृ मृत्युदर रोकने के लिए दशकों से चल रही योजनाएं प्रभावहीन होती नजर आ रही है। हर साल बच्चों की मौतों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बेहद डरावने हैं। देश में बच्चों की सेहत को लेकर राजनीति के बजाय राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता है। *(रा.प., 03.01.20 एवं दै.भा., 06.01.20)*

नहीं मिल रहे बेटियों के हक

प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस सरकारें बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं चला कर वाहवाही लूटती रहती है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारें ही लचर प्रक्रिया के चलते बेटियों को उनके हक नहीं दे पा रही। सरकार ने श्रमिकों की बेटियों के लिए श्रम विभाग के माध्यम से शुभ शक्ति योजना में शादी के लिए 55-55 हजार रुपए देने की योजना चला रखी है, लेकिन कई वर्षों से प्रदेश की सरकार एक लाख 64 हजार 788 बेटियों के 9 अरब 6 करोड़ 33 लाख 40 हजार रुपए पर कुण्डली मारे बैठी है।

अकेले दौसा जिले में 7 हजार 618 बेटियों को सहायता की दरकार है। श्रमिक अपनी बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के बाद भी चक्कर काट रहे हैं। *(रा.प., 19.01.20)*

महिलाओं की वित्तीय निर्णय में भागीदारी

एक सर्वेक्षण के अनुसार 68 प्रतिशत महिलाएं या तो अपने पैसे का प्रबंधन खुद कर रही हैं या अपने परिवारों के वित्तीय निर्णय में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। इन महिलाओं ने स्वीकार किया कि वह अपने वित्तीय फैसले खुद लेती हैं या अपने परिवार के वित्तीय निर्णयों में बराबर की भागीदारी रखती हैं।

ऑनलाइन वित्त सेवाएं उपलब्ध कराने वाली स्क्रिपबॉक्स के सर्वेक्षण के अनुसार केवल दस प्रतिशत महिलाएं ही वित्तीय निर्णय लेने की जिम्मेदारी अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य को सौंप देती है। सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर महिलाएं मासिक बचत के नियम को मानती है। केवल 30 प्रतिशत महिलाओं ने ही म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय विकल्पों में निवेश करने की बात कही। *(न.नु., 09.03.20)*

बेटी को सौंपी विकास की कमान

वह खुद गांव में बाइक से घर-घर जाकर लोगों से मिलने निकल जाती है और गांव के विकास के कामों के बारे में जानकारी लेती है। खासकर वह गांव की महिलाओं की समस्याओं को सुनती है और उनका निराकरण करने के प्रयास करती है।

भीलवाड़ा जिले की करेड़ा पंचायत समिति की ज्ञानगढ़ ग्राम पंचायत में 23 साल की सरपंच वर्षा टांक को वहां के लोगों ने गांव के विकास की कमान सौंपी है। वह प्रदेश के सबसे कम उम्र की सरपंचों में से एक है। उसका कहना है वह अपनी शादी से पहले गांव को बदलता हुआ देखना चाहती है। उसका जज्बा देख गांव वाले भी उसका साथ देते हैं। *(रा.प., 17.02.20)*

उपभोक्ता फैसले

भारी पड़ा पॉलिसी मेच्योर होने पर भुगतान नहीं करना

जयपुर जिले की गोविंदगढ़ निवासी सुनीता गुप्ता ने जिला उपभोक्ता मंच तृतीय में एलआईसी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद के अनुसार, 1984 में 50 हजार का बीमा कराया था। पॉलिसी 2004 में मेच्योर हो गई लेकिन उन्हें एलआईसी ने भुगतान नहीं किया।

मामले की सुनवाई पर एलआईसी ने जवाब में कहा कि बीमा 20 साल के लिए था। परिवादिया ने 11 वर्ष का ही 37 हजार 550 रुपए बतौर प्रीमियम जमा कराया। वर्ष 2004 में पॉलिसी की अवधि पूरी होने के आठ साल बाद 2012 में उन्होंने आरटीआई से जवाब मांगा और 2013 में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो समयावधि में नहीं है। परिवादी ने पॉलिसी परिपक्व (मेच्योर) होने के बाद समय पर मूल पॉलिसी बॉण्ड व डिस्चार्ज फार्म देकर भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

मंच ने फैसले में कहा कि एलआईसी ने परिवादिया को न तो बाकी प्रीमियम जमा कराने का नोटिस दिया और न ही भुगतान लेने के लिए पॉलिसी बॉण्ड व डिस्चार्ज फॉर्म की मांग की। मंच ने इसे एलआईसी का सेवा दोष मानते हुए आदेश दिया कि एलआईसी सुनीता गुप्ता को जमा प्रीमियम के 37 हजार 550 रुपए मय ब्याज के लौटाए और साथ ही 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना भी अदा करें। *(दै.भा., 03.01.20)*

दुर्लभजी अस्पताल को भारी पड़ी ऑपरेशन में लापरवाही

राज्य उपभोक्ता आयोग ने दुर्लभजी अस्पताल व डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत के मामले में दस लाख रुपए हर्जाना दिलाने के जिला उपभोक्ता मंच के फैसले को सही माना है।

मामले के अनुसार परिवादी राजेन्द्र अग्रवाल ने अपनी पत्नी आशा को बच्चेदानी में तकलीफ होने पर 22 जून 2005 को दुर्लभजी अस्पताल, जयपुर में भर्ती कराया था। जहां ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। राजेन्द्र अग्रवाल ने उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के बाद मंच ने दुर्लभजी अस्पताल व डॉक्टर को लापरवाही का दोषी माना और अस्पताल व डॉक्टर पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया था।

उपभोक्ता मंच के फैसले के खिलाफ दुर्लभजी अस्पताल व संबंधित डॉक्टर द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई गई। अपील में दलील दी गई कि ऑपरेशन के बाद कार्डियक अरेस्ट होने के चलते मरीज की मौत हुई थी, उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई। ऐसे में जिला मंच के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने उपभोक्ता मंच के फैसले को सही माना। आयोग ने दुर्लभजी अस्पताल व संबंधित चिकित्सक द्वारा पेश अपील को खारिज करते हुए आदेश दिए कि उपभोक्ता मंच के आदेशों की पालना की जाए और परिवादी राजेन्द्र अग्रवाल को दस लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा किया जाए। *(रा.प., 06.03.20)*

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित

'वर्तमान में हमें जागरूक उपभोक्ता के बजाय जागरूक एवं स्वस्थ ग्राहक के रूप में परिचित होना होगा, जो वस्तु को ग्रहण करता है। जिसका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है, वह स्वस्थ उपभोक्ता कहलाता है।'

उक्त विचार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च, 2020) के अवसर पर 'कट्स' एवं जिला रसद कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय विचार गोष्ठी में स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के जज प्रहलाद राय व्यास ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने सतत् उपभोक्ता और जैविक उत्पाद विषय को परिभाषित करते हुए बताया कि हमारी जैविक संपदा को बचाने और उसके उचित प्रबंधन के लिए सतत् उपभोक्ता बनने की शुरुआत करनी होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता आर.सी. शर्मा ने उपभोक्ताओं के कर्तव्य और अधिकारों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्यों का निर्वहन करते रहने से हम सजग और जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। विचार गोष्ठी में कृषि विभाग के उपनिदेशक ओ.पी.शर्मा ने जैविक खेती के फायदे और जैविक खेती की विधिवत प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

'कट्स' के समन्वयक गौहर महमूद ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उपवन संरक्षक शशि शंकर पाठक ने जैविक खेती और जैविक उत्पादों की आसानी से उपलब्धता और किसानों में जागरूकता लाकर उनकी लागत को कम करने के उपायों पर विचार करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर 'कट्स' मानव विकास केन्द्र परिसर में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के नन्द किशोर धाकड़, नारायण लाल धाकड़, मोहन लाल मेनारिया, फतेह लाल धाकड़, प्रतापगढ़ जिले के मांगी लाल जणवा, राधेश्याम तेली, बंशी लाल धाकड़, पारस धाकड़ और भीलवाड़ा जिले के हरी शंकर व्यास, रामेश्वर लाल बलाई, जमना लाल धाकड़ द्वारा कसूरी मेथी, काला चना, गेहूं, चना दाल, काचरी, बीज, टमाटर, काला गेहूं, पपीता, हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी मेथी, हल्दी, आंवला, नींबू व मटर सहित जैविक उत्पादकों की स्टाल लगा कर सहभागियों को जानकारी दी।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा–स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैरोबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)